एनडीए के समक्ष चुनौतियाँ

लेखक - आशिमा गोयल (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् में कार्यरत)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

25 मई, 2019

"इसे आपूर्ति की स्थितियों में सुधार करना चाहिए और किसान आय बढ़ाने के लिए कृषि रोजगार के अतिरिक्त अन्य रोजगारों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।"

भारतीय मतदाताओं ने केंद्र में एक स्थिर सरकार देने में उल्लेखनीय परिपक्वता और विचारशीलता दिखाई है। इस बार के चुनाव परिणाम से प्रतीत होता है कि मतदाताओं को एक स्थिर सरकार की अहमियत का एहसास हो गया है। 2014 में किया गया राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का पूर्वानुमान, जब मैक्रो अर्थव्यवस्था कमजोर थी, गलत साबित हुआ था। इस वर्ष भी इसी तरह के पूर्वानुमान कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हार के बाद लगाये गये थे, जो भी गलत साबित हुए।

चुनावी अनुमान लगाने वाले पंडितों को लोगों की बुद्धिमत्ता के आगे झुकना चाहिए क्योंकि इस चुनाव में भाजपा ने उन सभी राज्यों में भी जीत हासिल की, जिसकी भविष्यवाणी नहीं की गयी थी।

कांग्रेस ने सुशासन के लिए मतदाताओं की निरंतर आवश्यकता को कम करके आंका है। जब इनके पास विकल्प था तब कांग्रेस ने बेहतर मुख्यमंत्रियों का चुनाव नहीं किया। इन्होंने मतदाताओं की जरूरत को भी कम करके आंका। धीमी विकास दर और किसान संकट की बात नहीं की गई। इसके अलावा, इस चुनाव में न्यूनतम आय योजना (कांग्रेस का प्रस्तावित सामाजिक कल्याण कार्यक्रम) को रोजगार के विकल्प के रूप में जनता ने स्वीकार्य नहीं किया।

दूसरी ओर, भाजपा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से परे जाकर ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने का वादा किया और औसत नागरिक के आत्म-सम्मान और क्षमता को मजबूत किया, जो कि एक आकांक्षी भारत के लिए बिल्कुल सही दृष्टिकोण है।

चुनावी वादों में जान डाल दी

केंद्र में एक कमजोर सरकार चुने जाने की स्थिति में प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद का डर था। अब बुनियादी ढांचे, आवास, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, पर्यावरण पर अपने घोषणापत्र में दिए गए वादे के अनुसार भाजपा कार्य करेगी और किसान आय बढ़ाने के लिए कृषि रोजगार के अतिरिक्त अन्य रोजगारों की सुविधा प्रदान करेगी। ग्रामीण आय का केवल 23% ही अब कृषि से आता है। सरकार को प्रशासनिक सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पुलिस और न्यायिक सुधार पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। अच्छी तरह से लक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कुशलतापूर्वक कम लागत पर वास्तव में राहत प्रदान करेगा।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल अर्थव्यवस्था से है। वर्ष 2011 में शुरू हुई सख्त मौद्रिक और ऋण नीतियों के कारण रोजगार में वृद्धि काफी हद तक धीमी हो गयी थी। भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सिद्धांतों को आवश्यकतानुसार अनुकूलित नहीं किया गया था। विरासत में मिली गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का बोझ बढ़ता चला गया। चूंकि प्रमुख ऋण निजी व्यवसाय में दिए गए थे, इसलिए करदाताओं पर पड़ने वाले पूरे बोझ को रोकने के लिए एक दिवालियापन शासन लागू किया जाना जरूरी हो गया था।

लेकिन आज, कुछ कार्यवाही के साथ, मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है। हालांकि, अभी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के क्षेत्र में अभी भी तनाव है। इसलिए सरकार को विकास को समर्थन देने के लिए इस पर तेजी से कार्य करना चाहिए।

2011 के बाद से निजी निवेश की वृद्धि में तेजी आई है। नीति निर्धारक यह मान सकते हैं कि निजी निवेश अब पुनर्जीवित हो जाएगा और विदेशी धन देश में आ जाएगा। लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निजी निवेश में गिरावट आ सकती है क्योंकि वास्तविक ब्याज दरें बढ़ी हैं और तरलता तंग बनी हुई है। वैश्विक मंदी और व्यापार युद्धों (Trade War) से भी नुकसान हो रहा है।

एक व्यापक कर आधार

हालाँकि, आरबीआई अब अधिशेष तरलता को अधिशेष में रख रहा है, लेकिन एनपीए के साथ एक लंबी लड़ाई से डरे हुए बैंक उधार बढ़ाने के बजाय केवल आरबीआई के साथ ठहर गये हैं। यदि टिकाऊ तरलता की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, तो यह बैंकों को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और बाजार दरों में भी कमी लाएगा। आरबीआई की अनुमति के बावजूद, बैंक एनबीएफसी को ऋण नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे ऋण देने से अब डरते हैं। बैंकों के पूर्ण पुनर्पूंजीकरण, जो दिवालियापन और शासन में सुधार के साथ अब संभव है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा।

आरबीआई क्रेडिट जोखिम के कारण एनबीएफसी के लिए एक विशेष तरलता विंडो नहीं प्रदान करना चाहता है। उसका मानना है कि कमजोर एनबीएफसी को अब बाहर कर देने में ही भलाई है। लेकिन एनबीएफसी उपभोग वृद्धि और अचल संपत्ति का वित्तपोषण कर रहे थे, जो धीमी गति से चल रहे हैं, प्रणालीगत जोखिम पैदा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आरबीआई को कार्य करना चाहिए।

मौजूदा माहौल में मजबूत एनबीएफसी उधार देने के बजाय लिक्विडिटी को अपने हाथ में रखने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। यदि आरबीआई तरलता विंडो को उच्च दरों के साथ आनुषंगिक के खिलाफ उपलब्ध कराता है, तो इसका अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन तरलता की कमी का डर गायब हो जाएगा, जिससे एनबीएफसी को पुनर्जीवित करने में मद्द मिलेगी। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि राजकोषीय स्थान सीमित है।

विमुद्रीकरण और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) ने कर आधार को बढ़ा दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर कर चोरी कम हुई है। सरलीकरण और कर कटौती के बावजूद, चुनावों के बाद कर आधार से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। खर्च में मंदी के उलट होने के कारण शेष सरकारी नकद राशि खर्च की जाएगी। पूर्ण की गई योजनाओं से प्राप्त धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

विनम्रता के साथ शक्ति आनी चाहिए। असाधारण रूप से कठिन चुनावी मौसम के बाद, एनडीए रचनात्मक और समावेशी एजेंडे का पालन करेगी और मध्यम प्रगतिशील रुख को प्रोत्साहित करेगी। संस्थान किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। जनता को पता है कि सरकार ने सिस्टम को साफ करने के लिए कठिन फैसले लिए हैं और इसके कारण

GS World टीम...

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया गया।
- लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की घोषणा 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 को की गई थी।
- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/ स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

- यह राशि 2000 रुपए प्रत्येक की तीन किस्तों में दी जाएगी।
- यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। डीबीटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और किसानों का समय बचाएगा।
- प्रधानमंत्री-किसान योजना भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। योग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरण हेतु यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी हो गई है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। 01 फरवरी, 2019 तक जिनके भी नाम भूमि रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें इस योजना का लाभ लेने का पात्र माना जाएगा।

उद्देश्य

- प्रधानमंत्री-किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति पर अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निविष्टियों को प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।
- यह उन्हें ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचाएगी तथा कृषि कार्यकलापों में उनकी नियमितता भी सुनिश्चित करेगी।

किसे नहीं मिलेगा लाभ?

- यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों, किसी संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद् के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन में आते हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
- ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देश में रोजगार से जुड़ी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट लीक हुई।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा 6.1% के स्तर पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 की बेरोजगारी दर 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है।
- देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.8 फीसदी, जबकि ग्रामीण इलाकों में 5.3 फीसदी है।
- 15-29 साल के शहरी पुरुषों के बीच बेरोजगारी की दर 18.7 फीसदी है। 2011-12 में यह दर 8.1 फीसदी थी।
- 2017-18 में शहरी महिलाओं में 27.2 फीसदी बेरोजगारी है, जो 2011-12 में 13.1 फीसदी थी।
- एनएसएसओ सर्वे के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में

- पिछले सालों की तुलना में अभी देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है और यह कुल जनसंख्या के मुकाबले बहुत अधिक है।
- शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज्यादा रही। यहाँ बेरोजगारी दर पुरुषों में 18.7 प्रतिशत और महिलाओं में 27.2 प्रतिशत रही।
- पीएलएफएस एनएसएसओ का पहला सालाना हाउसहोल्ड सर्वे है, जिसके लिए जुलाई, 2017 से जून, 2018 के दौरान आंकड़े जुटाए गए थे।
- 2017-18 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में गिरावट देखी गई और यह 23.3 फीसदी रही, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 में यह 31.2 फीसदी और 2009-10 में 32.6 फीसदी रही।
- पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2011-12 में 79.8 फीसदी था, जो 2017-18 में 75.8 फीसदी रह गया। इसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं श्रम नौकरियों से बाहर हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 2017-18 में 13.6 प्रतिशत रही, जो 2011-12 में 4.8 प्रतिशत थी।
- शिक्षित ग्रामीण महिलाओं में 2004-05 से 2011-12 तक बेरोजगारी दर 9.7 प्रतिशत से 15.2 प्रतिशत के बीच रही है। 2017-18 में यह बढ़कर 17.3 प्रतिशत हो गई।
- शिक्षित ग्रामीण पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई, जो 2004-05 से 2011-12 के दौरान 3.5-4.4 प्रतिशत के बीच रही।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में 2011-12 के दौरान बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत थी, जो 2017-18 में तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई।

क्या है?

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नाम से भी जाना जाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।
- यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो नियमित रूप से देश का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में समाचारों में चर्चित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से किया गया
2. इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।
3. प्रधानमंत्री-किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति पर अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निविष्टियों को प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

2. हाल ही में समाचारों में चर्चित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की एक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों से अधिक दर्ज की गई है।
2. इस रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 की बेरोजगारी दर 1972-73 की बेरोजगारी दर के बाद सर्वाधिक दर्ज की गई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements regarding Prime Minister Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) scheme.

1. This scheme was launched from Gorakhpur (Uttar Pradesh) on February 24, 2019
2. Under this scheme, 6000 rupees per year will be given to joint and small joint venture / owned small and marginal farm households up to 2 hectares.
3. The objective of the Prime Minister-Kisan Yojana is to provide assistance in the financial needs of SMF in achieving various inputs to ensure proper crop health and good yields according to the estimated agricultural income at the end of each crop cycle.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 3
(c) 1 and 3
(d) 1, 2 and 3

2. Consider the following statements regarding a report of the National Sample Survey Office:

1. According to this report, unemployment rates in rural areas have registered more than urban areas in the country.
2. According to this report, the unemployment rate of 2017-18 was highest after the unemployment rate of 1972-73.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- वर्तमान में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. At present, what steps should the government take to deal with the problem of increasing unemployment? Discuss. (250 Words)

नोट : 23 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।